साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 31 मई 2021, वर्ष-7, अंक-09

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

- मंत्री यशोधरा बोलीं: 10 करोड़ मिले, काम जल्द शुरू कराएंगे
- डिजाइन पासः180 करोड़ की लागत, तीन चरणों में होगा काम
- अनलॉकः बाउंड्रीवॉल और ग्राउंड लेआउट का काम होगा शुरू
- पहले चरण में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल के साथ कोर्ट बनाए जाएंगे
- सरकार का दावः एक जगह 11 खेलों के खिलाड़ियों को मौका

चंबल में बनेगा मध्यप्रदेश का पहला खेल गांव

संवाददाता, भोपाल

चंबल का नाम आते ही जेहन में सबसे पहले डकैत या बागी की सूरत कल्पना की तरह सामने आ जाती है। चंबल घाटी के ये बीहड़ कभी डकैतों/बागियों के लिए अभयारण्य हुआ करते थे। जहां से वे डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाते। लेकिन अब इसी चंबल में शिवराज सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से मप्र का पहला राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल गांव बनाने जा रही है। दरअसल, खेल गांव बनाने के पीछे खेल मंत्री यशोधराराजे सिंधिया की सोच खेल के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाना है। इसके लिए ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ कुछ अन्य जिलों में इंटरनेशनल लेवल पर खेल सुविधाओं का विस्तार करना है। जिससे प्रदेश में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल गेम्स के साथ इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हो सकें।

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मप्र एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी कर सकेगा। प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ स्वीकृत कर दिए है। लॉकडाउन के बाद बाउंड्रीवाल सहित अन्य काम शुरू करेंगे।

-यशोधरा राजे सिंधिया, खेल मंत्री

50 एकड़ में बनेगा खेल गांव

खेल गांव का डिजाइन खेल विभाग ने पास कर दिया है। प्रदेश सरकार ने भी प्रथम चरण के कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद मप्र पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन बाउंड्रीवॉल के निर्माण कार्य के साथ ग्राउंड लेवलिंग का काम शुरू कर देगी। 50 एकड़ में तैयार होने वाले इस खेल गांव का काम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।

ग्वालियर करेगा मेजबानी

ग्वालियर भविष्य में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ नेशनल गेम्स की मेजबानी कर सकेगा। यही नहीं, फुटबॉल, स्वीमिंग, स्क्वैश, टेनिस, वालीबॉल, टीटी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, योगा और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को एक ही जगह मौका मिलेगा।

हॉकी मैदान भी रहेगा: खेल गांव में पहले चरण का काम बाउंड्रीवॉल और ग्राउंड लेआउट बनाने के साथ शुरू होगा। वहीं इंडोर स्पोर्ट्स हॉल भी बनेगा, जिसमें 6 सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट, अत्याधुनिक जिम, 6 टेबल-टेनिस टेबल, 5 पूल टेबल, दो स्क्वैश कोर्ट और दो योगा प्लेटफार्म भी बनेंगे।

केंद्र ने दी मंजूरीः गेहूं-चना के बाद मूंग भी समर्थन पर खरीदेगी शिवराज सरकार

सरकार ने बढ़ाया मूंग का मूल्य

- अब अन्नदाताओं से 7196 रुपए क्विंटल होगी खरीदी
- प्रदेश में पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई मूंग की बोवनी
- हरदा में इस साल सवा लाख हेक्टेयर में हुई मूंग की बोवनी
- 3500 करोड़ रुपए की फसल उत्पादन का अनुमान

संवाददाता, भोपाल

कोरोना संकट के दौरान किसानों को राहत देने के लिए शिवराज सरकार अब मूंग भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। अभी गेहूं, चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। मूंग के लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, विदिशा, रायसेन, जबलपुर सहित अन्य जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती बड़े पैमाने पर होती है। सिंचाई के साधनों का विस्तार होने के बाद प्रदेश में किसान अब तीन फसल लेने लगे हैं। मानसून से पहले मूंग की फसल आ जाती है और इससे होने वाली आमदनी से किसान सालभर की अपनी व्यवस्थाएं बना लेते हैं।

किसानों को मुनाफा

इस साल सरकार को समर्थन मूल्य पर मूंग की उपज बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 196 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सरकार ने समर्थन मूल्य सात हजार रुपए से बढ़ाकर 7196 रुपए कर दिया है। इसी सप्ताह मूंग बेचने के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मौसम अनुकूल रहने व रकबा ज्यादा होने के कारण इस साल होशंगाबाद संभाग में 3500 करोड़ रुपए का मूंग उत्पादन होने की उम्मीद है।

बढ़ा दिया था रकबा

हरदा और होशंगाबाद जिले में इस साल सिंचाई विभाग ने मूंग के लिए 70 हजार हेक्टेयर रकबे में तवा नहरों के जरिए बांध से पानी देने की बात कही थी। लेकिन दोनों जिलों में निजी व अन्य सिंचाई साधनों से ज्यादा रकबे में मूंग की बोवनी की। अकेले हरदा जिले में ही 1.25 लाख हेक्टेयर रकबे में मूंग की बोवनी हुई है। वहीं 1.50 लाख हेक्टेयर रकबा होशंगाबाद का है।

पिछले साल हुआ था घाटा

बीते साल सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के लिए घोषणा की थी। लेकिन अंत तक किसानों से मूंग की खरीदी नहीं की। इस कारण किसानों को मंडी में और व्यापारियों को खुले में मूंग बेचना पड़ा। इसका नुकसान यह हुआ कि व्यापारियों ने किसानों की मजबूरी को देखते हुए मूंग के दाम कम कर दिए थे।

खलेगी पानी की कमी

कृषि मंत्री ने हरदा जिले में टेल टू हेड पानी देने की बात कही थी। कई किसान तीसरे पानी को तरसते रहे। कुछ किसानों ने निजी पंपों से नहर में डाला, जिससे किसानों की फसल खराब न हो। मई में जो बारिश हुई, वो मूंग के लिए फायदेमंद रही। किसानों को भरपूर पानी नहीं मिलने से मूंग के दाने का आकार व चमक तथा वजन में अंतर आने की आशंका है।

इनका कहना है

मप्र सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समथर्न मूल्य पर करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति समथर्न मूल्य पर मूंग खरीदे जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य (एमसपी) 7 हजार 196 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्र ने मूंग की फसल का समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मप्र सरकार को मंजूरी प्रदान कर दी है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

चंबल के किसानों ने स्टाक की एक लाख क्विंटल सरसों

- ग्वालियर-चंबल अंचल में इस बार सरसों की बंपर पैदावार
- खुले बाजार में दाम सरकार के समर्थन मूल्य से दोगुना मिला
- सरसों के दाम इतिहास में पहली बार 7000 रुपए क्विंटल

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल में इस बार सरसों की बंपर पैदावार हुई है। बाजार में दाम सरकार के समर्थन मूल्य से लगभग दोगुना है। इस कारण किसानों ने सरकार को सरसों का एक भी दाना नहीं बेचा। मुरैना में हजारों किसानों ने सरसों के भाव और बढ़ने की उम्मीद में एक लाख क्विंटल सरसों को स्टाक कर रखा है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश व हरियाणा में सरसों की पैदावार देश में सबसे ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में जितनी सरसों होती है, उसकी 70 फीसद पैदावार ग्वालियर-चंबल (मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया व श्योपुर जिलों) में होती है। मुरैना में इस बार 1 लाख 52 हजार 656 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 लाख 50 हजार क्विंटल से ज्यादा सरसों की पैदावार हुई है। रकबा व पैदावार ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो भाव भी पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना हो गया।

समर्थन केंद्र नहीं पहुंची सरसों

सरकार ने समर्थन मूल्य पर सरसों के दाम 4650 रुपए प्रति क्विंटल रखा, परंतु जैसे ही सरसों खेतों से कटकर कृषि मंडियों में आने लगी, बाजार में दाम अचानक 5000 रुपए क्विंटल पहुंच गए, जो बढ़ते हुए 7400 रुपए तक हो गए है। यही कारण रहा कि, मुरैना के किसी भी किसान ने समर्थन मूल्य पर सरसों नही बेची। जिले के किसान अब तक साढ़े 5 से पौने 6 लाख क्विंटल सरसों व्यापारियों को बेच चुके है।

आसमान छू रहे सरसों के दाम: केंद्र सरकार ने 8 जून 2021 से तेल कारोबारियों के मिश्रित तेल के लाइसेंस खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा विदेशों से आने वाले पाम आयल, राइसब्रान आयल और सोया आयल पर आयात शुल्क बढ़ गया है। इससे इन तेलों का आयात लगभग बंद हो गया है। इस कारण सरसों की मांग बाजार में इतनी बढ़ी कि तेल कारोबारियों ने सरसों का स्टाक करना शुरू कर दिया और सरसों के दाम इतिहास में पहली बार 7000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा पहुंच गए है।

महामारी में महंगाई: पहली बार राजधानी में सेब 300 और संतरा 200 रुपए किलो

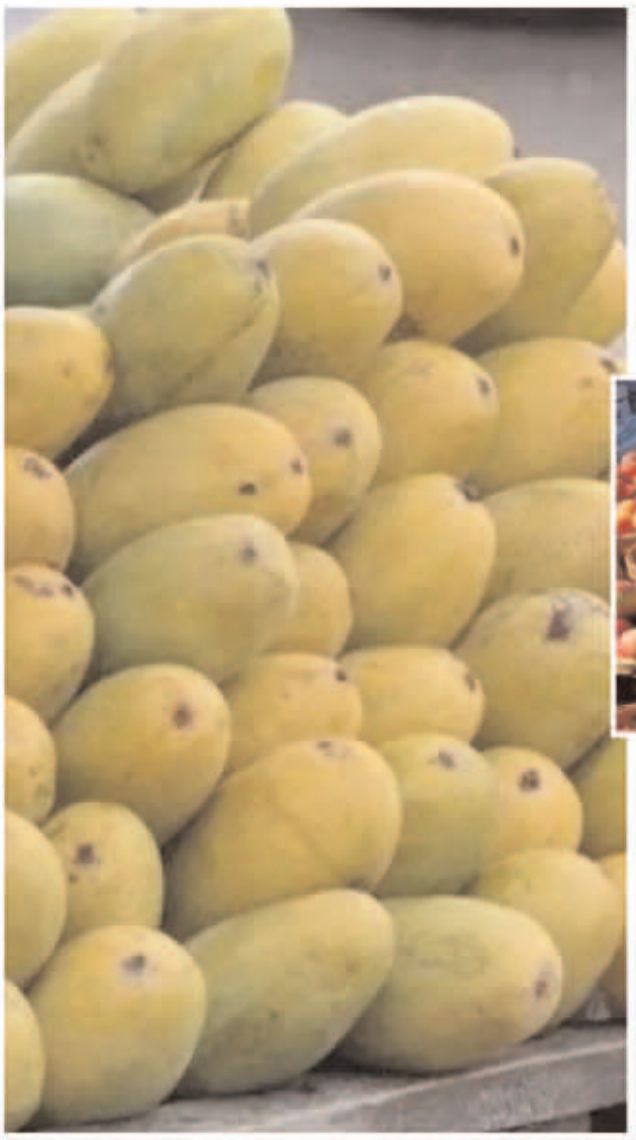

भोपाल में प्रति दिन 40 ट्रक आम की हो रही खपत

मुंह में पानी ला रहा आम, बाजार में 80 रुपए किलो

संवाददाता, भोपाल

राजधानी में कोरोना महामारी के बीच सेब और संतरे के भाव रिकॉर्ड बढ़े हुए हैं। सीजन में पहली बार सेब 300 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, जबकि संतरा 200 रुपए किलो तक है। बावजूद कोरोना संक्रमण के चलते लोग इन्हें खा रहे हैं। शहर में प्रतिदिन दो हजार पेटी सेब-संतरा बिक रहा है। इधर, आम और तरबूज लोगों के मुंह में पानी ला रहा है। इंदौर मंडी बंद होने से भोपाल में आम की प्रतिदिन की आवक 40 ट्रक (प्रति ट्रक औसत 25 क्विंटल) हो गई है। थोक में 30 से 40 रुपए तो फुटकर में यह 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। आंध्रप्रदेश से बादाम, लंगड़ा आदि आम की किस्में आ रही हैं। इंदौर मंडी बंद होने से आवक बढ़ गई है। इससे थोक भाव 30 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। कर्फ्यू खुलने के बाद आवक बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्तरप्रदेश से भी आवक बढ़ेगी। यहां से आसपास के जिलों में भी आम भेजा जा रहा है।

विदेशी सेब की आवक

शहर में सेब की एक हजार पेटी (प्रति पेटी औसत 12 किलो) की आवक है। कारोबारियों ने बताया कि विदेशों से मुंबई में सेब आ रहा है, जो ट्रकों के माध्यम से यहां लाया जा रहा है। इससे थोक भाव 250 रुपए प्रति किलो तक है। अगस्त माह से कश्मीर व हरियाणा से सेब की आवक होगी। इसके बाद भाव कम होंगे। वहीं प्रतिदिन 1200 पेटी संतरे की आवक है। 130 से 150 रुपए किलो तक थोक भाव है। तरबूज की आवक भी अच्छी है।

यह चल रहे फलों के भाव

फल	किलो में भाव
सेब	270 से 300 रुपए
संतरा	180 से 200 रुपए
आम	60 से 80 रुपए
पपीता	50 से 60 रुपए
अंगूर	80 से 100 रुपए

नारियल पानी की खपत बढ़ी

कोरोना संक्रमण के चलते लोग नारियल पानी की पीना पसंद कर रहे हैं। इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई है। 60 से 70 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचा जा रहा है।

बालाघाट में आम की पैदावार ने बनाया आत्मनिर्भर

- किसान ने सात साल में तैयार किया आम का बगीचा
- दस एकड़ में आम की दस किस्मों के एक हजार पेड़
- सालाना 10 लाख रुपए की ले रहे आम की फसल
- छह एकड़ में लगा रहे धान की फसल
- आठ क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हो रही धान
- 25 क्विंटल चावल तैयार कर बाजार में बेचा
- 350 रुपए किलो में बेचा काला चावल

एक किसान ने दस एकड़ में तैयार किया बगीचा

इधर, धान उत्पादक बालाघाट जिले में किसान कृषि में बदलाव लाने के लिए उन्नत प्रयोग कर रहे हैं। धान के खेतों में आम की फसल ले रहे हैं। जिले के गर्रा के किसान विशाल बिसेन ने 10 एकड़ के खेत में एक हजार आम के पौधे रोपकर बगीचा तैयार कर दिया है। उसने न केवल खेतों में हरियाली बढ़ाई है,बल्कि आम की खास किस्मों से मुनाफा भी बढ़ाया है। इतना ही नहीं, इन्हीं आम के पेड़ों के बीच में खाली जगह में ब्लैक राइस की भी फसल ले रहे हैं।

जो धान की खास किस्म चिन्नौर के चावल से भी अधिक मुनाफा दे रही है। गर्रा के इस किसान की पर्यावरण सरंक्षण की यह कोशिश न केवल खेतों में हरियाली बढ़ा रही है,बल्कि इसने मुनाफा भी बढ़ाया है। आम के से धान की फसल कृषि के क्षेत्र में समृद्धि भी ला रही है। इससे प्रेरित होकर आसपास के किसान भी अब ब्लैक राइस की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं।

इनका कहना है

जिला धान उत्पादक है। यहां धान की उन्नत किस्में लगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इन्ही किस्मों में ब्लैक राइस भी खास है। जो दीगर किस्मों से अधिक मुनाफे की फसल है। ढाई लाख हेक्टेयर खरीफरकबा की तुलना में यह मामूली रकबे में लेकिन अब करीब ढाई सौ एकड़ में इसकी खेती हो रही है। करीब सवा सौ किसान इसकी फसल लगा रहे हैं। महंगी होने से अब किसान इसका रकबा भी बढ़ा रहे हैं। गर्रा में किसान इसका रकबा बढ़ा रहे हैं।

सीआर गौर, प्रभारी उपसंचालक कृषि विभाग

दस लाख सालाना आमदनी

किसान की मानें तो पहले वह खरीफसीजन में धान की ही एक फसल ले पाते थे, लेकिन अब आम का बगीचा तैयार कर वह आम की फसल से भी सालाना 10 लाख रुपए की आमदनी ले पा रहे है,और उसकी खेत में छह एकड़ में ब्लैक राइस के लिए धान लगा रहे हैं। जिसका चावल तैयार कर बाजार में बेचकर पहले ही साल सात लाख से अधिक उत्पादन हुआ है। जो दीगर धान की तुलना में कई ज्यादा है। इसी खेत की मेढ़ पर व तुअर की फसल भी ले रहे हैं।

आम की किस्में

गर्रा में किसान ने दस एकड़ में दशहरा, लंगड़ा, चदसा, आम्रपाली, बैगन फल्ली, मल्लिका, ग्रीन बॉम्बे समेत दस किस्मों का बगीचा तैयार किया है। जो आसपास के किसानों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है।

इंदौर की गौशालाओं में पशु आहार और चारे-भूसे का संकट

संवाददाता, इंदौर

जिले की अधिकांश गौशालाओं में गौवंश के लिए पशु आहार, चारे-भूसे का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कहीं भी भूसा आसानी से उपलब्ध नहीं है। जहां कहीं थोड़ा बहुत मिल भी रहा है तो गत वर्ष के मुकाबले दो गुने दामों पर। हर वर्ष भूसे की कीमत 3.50 से ले कर चार रुपए प्रति किलो तक रहती है, लेकिन इस बार वर्तमान में भाव सात से आठ रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अधिकांश गौशालाओं में भूसे का स्टाक खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इससे चिंतित मां पराम्बा गो भक्त मंडल के संयोजक योगेश होलानी, अमोल जिंदानी और मुकेश गुप्ता ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है। जिसमें कहा है कि जनप्रतिनिधि अपनी विधायक निधि अथवा अन्य किसी कोष से आर्थिक सहायता दे कर गायों के लिए आहार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करें। गौशालाओं में पशु आहार की समस्या आने वाले दिनों में विकराल रूप ले सकती है।

» मां पराम्बा गो भक्त मंडल ने जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार

» साढ़े तीन रुपए मिलने वाला भूसा अब 7 रुपए किलो

कमी का कारण

दरअसल, इस बार गेहूं कटाई के सीजन में बारिश होने से अधिकांश किसानों ने अपनी फसल को हार्वेस्टर की मदद से कटवाया है। इस कारण भूसे की कमी हो गई है। इसके अलावा अनेक व्हाइट कोल निमार्ताओं ने भी किसानों से सीधे-सीधे भूसा खरीद लिया है। व्हाइट कोल का उपयोग होटलों और अन्य कारखानों आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है।

भाव भी दो गुना

कारखानों में व्हाइट कोल के प्रयोग से ज्यादा धुंआ नहीं होता है, इसलिए अधिकांश शहरी उपभोक्ता व्हाइट कोल के ग्राहक बनते जा रहे हैं। हालात यह हैं कि अब दो गुने भावों में भी भूसा नहीं मिल पा रहा है। जिले की अधिकांश गौशालाओं में भूसे का स्टाक एकाध सप्ताह का ही बचा रह गया है।

मदद के लिए बढ़ाए हाथ

मां पराम्बा गो भक्त मंडल ने अपने स्तर पर कुछ समाजसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से संपर्क कर कुछ गौशालाओं के लिए भूसे की व्यवस्था की है। इनमें माहेश्वरी कपल क्लब, मोहिनीदेवी मदनलाल समदानी पारमार्थिक ट्रस्ट मुम्बई, जिंदाखेड़ा के पंकज दुबे, समाजसेवी मुकेश अग्रवाल, वासुदेव मालू, गोपाल राठी, मनोज चंडक, रवि पांडे, मनीष गुप्ता आदि ने गौशालाओं की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं।

50 गौशाला का लक्ष्य

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदस्य हुकमचंद सावला के मार्गदर्शन में मंडल के प्रयासों से जिले की खजूरिया, सिकंदरी, हातोद, गांधीनगर, गंगाजलखेड़ी, देवड़ाखेड़ी, कनवासा, देपालपुर एवं गौतमपुरा की गौ शाला में 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भक्त मंडल ने इस वर्ष के अंत तक 50 गौशालाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा है।

किसानों से 200 करोड़ बकाया की वसूली करेंगी समितियां

» सिंचाई के पानी की वसूली के लिए एनवीडीए ने कसी कमर

» समितियां बांध और नहरों के संधारण व संचालन भी करेंगी

संवाददाता, भोपाल

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उद्योग और सिंचाई के पानी का किसानों पर 200 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इसकी वसूली किया जाना है। विभाग ने इसकी वसूली के लिए अब पांच सौ से ज्यादा समितियां गठित की है। यह समितियां बकाया राशि तो वसूलेंगी। साथ ही बांध और नहरों के संधारण तथा संचालन का भी काम करेंगी। दरअसल, एनवीडीए का उद्योगों और सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करने वाले किसानों से जल की राशि वसूल किया जाना है। यही वजह है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 के तहत जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन करना पड़ रहा है। खास बात है कि एनवीडीए ने पहली बार जल संसाधन विभाग की ही तर्ज पर इन जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया है।

नहरों के लिए गठित संस्थाएं

विभाग ने अपनी सिंचाई परियोजनाओं तथा नहरों के संधारण और संचालन के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया है। यह संस्थाएं जिन नहरों का संस्थाओं का संधारण करेंगी उनमें इसमें कटनी जिले की 13, नरसिंहपुर जिले की 60, रीवा में 12, सतना में 85, खरगोन में 43, बड़वानी में 24, इसी तरह ओंकारेश्वर के लिए 37, धार में 43, नर्मदा मालवा लिंक के तहत इंदौर में 18 और उज्जैन में आठ जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया है।

बांधों के लिए दस समितियां: जिन महत्वपूर्ण बांधों के लिए समितियां गठित की गई हैं उनमें इंदिरा सागर के लिए 30, बरगी व्यपवर्तन 29, रानी अवंती बाई 30, अपरवेदा परियोजना 09, ओंकारेश्वर 01, पुनासा उद्वहन 18, नर्मदा मालवा लिंक 18, मान परियोजना 10, जोबट परियोजना 06 और हालोन परियोजना के लिए 10 समितियां गठित की गई है।

जर्जर बांधों को 551 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार

» सिंचाई क्षमता बढ़ाने रख-रखाव की चल रही तैयारी

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के प्रयासों के तहत अब जर्जर हो चुके दो दर्जन से अधिक बाधों का नए सिरे से रखरखाव किए जाने की कवायद चल रही है। इन बांधों से संवारने के लिए सरकार छह अरब की राशि खर्च करेगी। यह राशि सिंचाई विभाग कर्ज के माध्यम से जुटाएगा। यह वे बांध हैं जिनका निर्माण हुए करीब पांच दशक से अधिक का समय हो चुका है। इन बांधों का रख-रखाव करने के साथ ही नए सिरे से कुछ इलाकों में नहरों का निर्माण भी किया जाएगा। सरकार द्वारा विश्व बैंक से कर्ज लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें 20 फीसद राशि का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। 551 करोड़ के खर्च के बाद प्रदेश में करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन में नए सिरे से सिंचाई सुविधा बढ़ जाएगी। दरअसल, लंबे समय से रखरखाव न होने की वजह से इन बांधों के गेट से लेकर पाल तक जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। इन सभी का सुधार कार्य किया जाना जरुरी हो गया है। इस कर्ज के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदेश सरकार को स्वीकृति दी जा चुकी है।

पहले खर्च किया था 1900 करोड़: गौरतलब है कि डेढ़ दशक पहले भी प्रदेश सरकार ने इसी तरह के कई बेहद पुराने बांधों की मरम्मत पर कर्ज लेकर 1900 करोड़ व्यय किए थे। उस समय भी अधिकांश पैसा नहरों के निर्माण पर खर्च किया गया था। यही वजह है कि अब प्रदेश में सिंचाई विभाग के पास 33 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई की सुविधा मौजूद है।

इन बांधों को संवारेंगे: जिन पुराने बांधों का रखरखाव किया जाना है उनमें भगवंत सागर, चंदिया तालाब, बीरपुर तालाब, गांधी सागर बांध, हथसाई खेड़ा बांध, चोरल परियोजना, चंदोरा परियोजना, गाडगिल सागर परियोजना, केरवा बांध, माही परियोजना, नंदनवारा तालाब, वीर सागर, बहोरी बांध परियोजना, राजधाट परियोजना, यसाकाल्दा तालाब, मनसूरवारी परियोजना आदि शामिल है। इसमें भी सबसे अधिक राशि 286 करोड़ से अधिक गांधी सागर परियोजना पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

टॉप 50 परफॉर्मर में मप्र के सात सांसद, उज्जैन के सांसद फिरोजिया 8वें स्थान पर , तोमर, प्रज्ञा और सुधीर ने मनवाया लोहा

संसद में एमपी के सांसदों ने दिखाया दम

भोपाल। देश के सांसदों की अब तक के कार्यकाल के दौरान लोकसभा से लेकर धरातल तक कैसा प्रदर्शन रहा है, इसे लेकर रेटिंग और रैंकिंग जारी हुई है। पार्लियामेंट्री बिजनेस डॉट कॉम द्वारा जारी सूची का आंकलन करने पर मप्र के सांसदों की परफॉर्मेंस अन्य राज्यों के सांसदों से बेहतर रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में मप्र के 7 सांसद टॉप 50 में शामिल हुए हैं। उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया 8वें स्थान पर हैं। वर्तमान में देश के 5 लोकसभा सांसदों में से मप्र के 29 सांसदों में से 28 सांसदों (स्व. नंदकुमार सिंह चौहान को छोड़कर) की लोकसभा में उपस्थित, प्रश्न, वाद-विवाद, गैर सरकारी विधेयक, संसद क्षेत्र में उपस्थिति, विकास कार्यों में रुचि, जन समस्याओं के प्रति गंभीरता, सार्वजनिक छवि के आधार पर परफॉर्मेंस का आंकलन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि इस बार मप्र के सांसदों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

संध्या राय: भिण्ड की सांसद संध्या राय की संसद में उपस्थिति 75.86 प्रतिशत रही। इसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं माना जाता है। वहीं सवाल पूछने और डिबेट में इनकी भागीदारी खराब रही। इन्होंने इस बार संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। वही 2 डिबेट में वे भागीदार बनीं। वहीं संसदीय क्षेत्र में इनकी सक्रियता भी कम रही। पब्लिक रेटिंग में भी इनकी पूअर परफॉर्मेंस रही। इन्हें एक भी अंक नहीं मिला है।

विवेक नारायण शेजवलकर: ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर की संसद में उपस्थिति 96.55 फीसदी रही। जबकि सवाल पूछने में ये फिसड्डी रहे। सदन में इन्होंने मात्र 5 सवाल पूछे। इनकी परफॉर्मेंस 3.45 प्रतिशत रही। डिबेट में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और इन्होंने 7 डिबेट में भाग लिया। क्षेत्र के विकास में इनकी परफॉर्मेंस चिंताजनक है। पब्लिक रेटिंग में इनकी स्थिति दयनीय है। इन्हें जनता ने कोई रैंक नहीं दिया है।

केपी यादव: गुना सांसद केपी यादव प्रदेश की संसद में परफॉर्मेंस अच्छी रही और उनकी उपस्थिति 100 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 40 सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 27.59 प्रतिशत रही, तो ये 9 डिबेट में शामिल हुए। पब्लिक रेटिंग में इनको कोई अंक नहीं मिला है।

राजबहादुर सिंह: सागर सांसद राजबहादुर सिंह की संसद में उपस्थिति 82.76 प्रतिशत रही। वहीं सवाल पूछने और डिबेट में इनकी परफॉर्मेंस शून्य रही। हालांकि क्षेत्र में ये सक्रिय हैं लेकिन इनकी विकास कार्य में भागीदारी चिंतनीय है। इनकी पब्लिक रेटिंग भी चिंतनीय है।

डॉ. वीरेंद्र कुमार: सातवीं बार टीकमगढ़ सांसद बने वीरेंद्र कुमार की संसद में उपस्थिति 100 प्रतिशत रही। वहीं इन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा है। इन्होंने 16 डिबेट में भाग लिया। क्षेत्र में अच्छी पकड़ के बाद भी विकास कार्य करवाने में इन्होंने कंजूसी दिखाई है। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य है।

विष्णुदत्त शर्मा: खजुराहो सांसद शर्मा की संसद में उपस्थिति 55.17 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा, जबकि 2 डिबेट में शामिल हुए। इनकी पब्लिक रेटिंग 2.5 प्रतिशत रही।

गणेश सिंह: सतना सांसद गणेश सिंह की संसद में उपस्थित 79.31 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 19 सवाल पूछे और इनका परफॉर्मेंस 13.1 प्रतिशत रही। इन्होंने 7 डिबेट में भाग लिया। वहीं इनकी पब्लिक रेटिंग 4.01 प्रतिशत है। भाजपा के अन्य सांसदों की अपेक्षा इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य सबसे अधिक करवाया है। दरअसल, इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के अंतिम दिनों में कई विकास कार्यों के लिए फंड आवंटित किया था, जिससे उनकी इस पारी में काम हुए हैं।

जनार्दन मिश्रा: रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की संसद में उपस्थिति 96.55 प्रतिशत रही। वहीं सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 1.38 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में मात्र 2 सवाल पूछे। वहीं ये 4 डिबेट में शामिल हुए। इनकी पब्लिक रेटिंग 3.13 प्रतिशत रही।

रीति पाठक: सीधी सांसद रीति पाठक की संसद में उपस्थिति 93.1 प्रतिशत रही। वहीं सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 17.14 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 25 सवाल पूछे हैं। ये 7 डिबेट में भी शामिल रहीं। संसदीय क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता बढ़ी है लेकिन विकास कार्य कराने में ये फिसड्डी रही हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग 4.34 प्रतिशत रही।

लोकप्रिय सांसदों में मप्र के 13 सांसद

देश के लोकप्रिय सांसदों में मप्र के 13 सांसद शामिल हैं। इस बार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने पब्लिक रैंकिंग में परे 5 अंक हासिल करके अपना लोहा मनवाया है। और देश के लोकप्रिय सांसदों में स्थान पाया है। पब्लिक रैंक में राजस्थान के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल देश में नंबर-1 स्थान पर हैं। अगर मप्र की बात करें तो सतना सांसद गणेश सिंह 11वें स्थान पर, सीधी सांसद रीति पाठक 67 स्थान पर रहीं। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, गजेंद्र सिंह पटेल, रमाकांत भार्गव, हिमाद्री सिंह, नकुलनाथ, छतरसिंह दरबार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार सक्रिय रहीं। वहीं खजुराहो सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी सक्रियता तथा कार्यप्रणाली से लोकप्रियता हासिल की है। कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। इनकी पब्लिक रेटिंग 4.3 है।

मप्र सांसदोंं परफॉर्मेंस

17वीं लोकसभा दूसरे बजट सत्र के दौरान मप्र के 28 सांसदों में अधिकांश ने संसद में अपनी सक्रियता का परिचय किया। सांसदों ने सवाल पूछने और डिबेट में तर प्रदर्शन किया है। संसदीय क्षेत्र में भी इनकी रुचता बराबर बनी रही। वहीं कुछ सांसद ऐसे भी जिनका इस बार प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। सूत्र बताते की भाजपा का केंद्रीय संगठन ऐसे सांसदों को एक बार फिर से उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका देगा।

अनिल फिरोजिया टॉप 10 में

संसद और सांसदों के कामकाज पर केन्द्रित वेबसाइट ह्यपार्लियामेंट्री बिजनेस डाट काम्ह के अध्ययन के मुताबिक मप्र के 29 सांसदों में से 7 सांसद ऐसे हैं जो देश में ओवरऑल टॉप 50 में जगह बना पाए हैं। इनमें उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया 8वें स्थान पर आए हैं और देश के टॉप-10 बेहतर सांसदों में शुमार हुए हैं। इनके अलावा जनार्दन मिश्रा 13वें नंबर पर, उदयप्रताप सिंह 26वें नंबर पर, महेंद्र सिंह सोलंकी 38वें नंबर पर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर 40वें नंबर पर, छतरसिंह दरबार 43 नंबर पर और गणेश सिंह 46वें नंबर पर आए हैं। मप्र के जो 7 सांसद टॉप 50 में शामिल हैं, उनमें से अनिल फिरोजिया, महेंद्र सिंह सोलंकी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहली बार सांसद बने हैं। वहीं जनार्दन मिश्रा, सुधीर गुप्ता दूसरी बार, उदयप्रताप सिंह और छतरसिंह दरबार तीसरी बार तथा गणेश सिंह चौथी बार सांसद बने हैं। इस सांसदों ने सदन से लेकर अपनी संसदीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर: भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह की संसद में उपस्थिति 68.97 प्रतिशत रही है। इन्होंने सदन में 10 सवाल पूछे है और इनकी परफॉर्मेंस 6.9 प्रतिशत रही। जबकि 5 डिबेट में शामिल हुईं। इनकी पब्लिक रेटिंग सर्वाधिक 5 रही।

राकेश सिंह: जबलपुर सांसद राकेश सिंह की संसद में उपस्थिति 100 प्रतिशत रही। वहीं सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 20 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 29 सवाल पूछे। वहीं ये 5 डिबेट में शामिल हुए। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही।

नकुलनाथ: छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की संसद में उपस्थिति 72.41 प्रतिशत रही है। इन्होंने 1 भी सवाल नहीं पूछा है। ये 1 डिबेट में भी शामिल नहीं हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग 4.3 प्रतिशत रही है।

हिमाद्री सिंह: शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की संसद में उपस्थिति 100 प्रतिशत रही है। सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 10.34 प्रतिशत रही, यानी इन्होंने 15 सवाल पूछे। वहीं ये 2 डिबेट में शामिल हुईं। इनकी पब्लिक रेटिंग 3 प्रतिशत रही।

ढाल सिंह बिसेन: बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन की संसद में उपस्थिति 96.55 प्रतिशत रही। इनकी सवाल पूछने में 8.97 प्रतिशत परफॉर्मेंस रही है। वहीं ये 7 डिबेट में शामिल हुए। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही है।

उदयप्रताप सिंह: तीसरी बार होशंगाबाद से सांसद बने उदयप्रताप सिंह की संसद में उपस्थिति 86.21 प्रतिशत रही। सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 17.24 प्रतिशत रही। वहीं ये 4 डिबेट में शामिल हुए। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही।

रमाकांत भार्गव: विदिशा से पहली बार सांसद बने भार्गव की संसद में उपस्थिति 79.3 प्रतिशत रही है। जबकि सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 13.1 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 19 सवाल पूछे। ये 1 डिबेट में शामिल हुए। वहीं इनकी पब्लिक रेटिंग 2.47 प्रतिशत रही।

रोडमल नागर: राजगढ़ से दूसरी बार सांसद बने रोडमल नागर की संसद में उपस्थिति 65.52 प्रतिशत रही। वहीं सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 13.1 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 19 सवाल पूछे हैं। वहीं ये 1 डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य है।

महेंद्र सिंह सोलंकी: देवास सांसद सोलंकी की संसद में उपस्थिति 96.55 प्रतिशत रही। वहीं इन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा है। जबकि 2 डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही है।

अनिल फिरोजिया: उज्जैन सांसद फिरोजिया की संसद में उपस्थिति 75.86 प्रतिशत रही। जबकि सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 31.72 प्रतिशत रही है। इन्होंने 46 सवाल पूछे हैं। वहीं ये 2 डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही है।

सुधीर गुप्ता: मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता अपनी दूसरी पारी में भी प्रदेश के सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। इनकी संसद में उपस्थिति तो 86.21 प्रतिशत रही ही है, वहीं प्रदेश के एकमात्र सांसद हैं जिनकी सवाल पूछने में परफॉर्मेंस अच्छी मानी गई है। इनकी परफॉर्मेंस 64.19 प्रतिशत रही। इन्होंने कुल 93 सवाल पूछे हैं। वहीं 2 डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग पूरे 5 रही है।

गुमान सिंह डामोर: रतलाम सांसद डामोर की संसद में उपस्थिति 68.97 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा है। जबकि एक डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही है।

छतरसिंह दरबार: धार सांसद दरबार की संसद में उपस्थिति 55.17 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा है। न ही डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग 1 रही है।

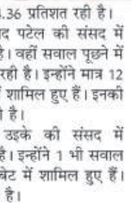

शंकर लालवानी: इंदौर सांसद लालवानी की संसद में उपस्थिति 86.21 प्रतिशत रही है। जबकि सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 8.97 प्रतिशत रही है। इन्होंने कुल 13 सवाल पूछे हैं। वहीं 7 डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग 4.36 प्रतिशत रही है।

गजेन्द्र सिंह पटेल: खरगोन सांसद पटेल की संसद में उपस्थिति 72.41 प्रतिशत रही है। वहीं सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 8.28 प्रतिशत रही है। इन्होंने मात्र 12 सवाल पूछे हैं। वहीं 3 डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग 3.6 प्रतिशत रही है।

दुगार्दास उइके: बैतूल सांसद उइके की संसद में उपस्थिति 96.55 प्रतिशत रही है। इन्होंने 1 भी सवाल नहीं पूछा है। जबकि ये 2 डिबेट में शामिल हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही है।

पारंपरिक बनाम एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर विवाद, सभी उपचार विधियों की अपनी महत्ता

महामारी के इलाज में सबसे कारगर हथियार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता ही सामने आई है, और इसे बड़ाने में एलोपैथ के साथ साथ पारंपरिक उपचार पद्धतियों का उल्लेखनीय योगदान सामने आया है। ऐसे में कोरोना वायरस जनित संक्रमण के उपचार में कौन सी पद्धति कितनी कारगर रही, इस पर एलोपैथ के पैरोकारों और बाबा रामदेव के बीच किच-किच जारी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के दबाव में बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से माफी मांग ली।

यह सही है कि कोरोना महामारी के इलाज में सबसे कारगर हथियार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता ही सामने आई है, और इसे बड़ाने में एलोपैथ के साथ साथ पारंपरिक उपचार पद्धतियों का उल्लेखनीय योगदान सामने आया है। ऐसे में कोरोना वायरस जनित संक्रमण के उपचार में कौन सी पद्धति कितनी कारगर रही, इस पर एलोपैथ के पैरोकारों और बाबा रामदेव के बीच किच-किच जारी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के दबाव में बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से माफी मांग ली। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने 25 सवालों की सूची जारी करके एक तरह से आइएमए को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। टीवी चैनलों की बहस में आइएमए के कर्ता-धर्ता बाबा से भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाबा के सवालों का जवाब नहीं दे पाया है।

अगर बाबा जोर देने लगते हैं तो बहस में शामिल डॉक्टर विज्ञानी नहीं होने की बुनियाद बताते हुए उन्हें खारिज करने की कोशिश करते हैं। परंतु इस पूरे विवाद ने देसी एवं पारंपरिक इलाज पद्धति बनाम एलोपैथी के बीच विवाद छेड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि पत्रकारिता के छात्रों को सूचना के साम्राज्यवाद के बारे में पड़ाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यजनक तथ्य यह है कि मौजूदा मीडिया में सक्रिय ज्यादातर लोग सूचना के इसी साम्राज्यवाद के जाने-अनजाने वाहक हैं। इसलिए उन्हें पता नहीं है कि पारंपरिक बनाम एलोपैथी का विवाद कोरोना की पहली लहर के दौरान उसी पश्चिम में भी हुआ था जिसे हम आधुनिक और श्रेष्ठ सभ्यता मानते हैं। विवाद अफ्रीकी देशों में भी कम नहीं हुआ था। लेकिन पश्चिमी दुनिया से जिन माध्यमों के जरिये हमारे पास सूचनाएं आती हैं, चूंकि वे पश्चिम की श्रेष्ठता ग्रंथि से पीड़ित हैं, जो पश्चिमी आर्थिक मॉडल और हितों की परोक्ष रूप से हिफाजत ही करते हैं, इसलिए उनकी ओर से कथित विकासशील समाजों में ऐसी सूचनाएं नहीं आईं। यही वजह है कि बाबा रामदेव बनाम एलोपैथी के विवाद में भारतीय सूचना तंत्र भी बाबा के खिलाफ और आइएमए के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है।

बाबा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जो बहसबाजी हो रही है, उसकी व्याप्ति आयुर्वेद बनाम आधुनिक चिकित्सा पद्धति होती जा रही है। अव्वल तो संकट के समय ऐसा कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। कोई भी पद्धति न तो पूर्ण हो सकती है और न ही सटीक। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि किसी पद्धति को अवैज्ञानिक कह कर खारिज कर दिया जाए। अगर आयुर्वेद या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति इतनी ही अवैज्ञानिक थी तो विज्ञानी होने का दावा करने वाली पश्चिमी सभ्यता के तमाम लोग इसके मुरीद क्यों होते चले गएड़ कोरोना महामारी काल में निश्चित तौर पर सभी चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टरों ने मेहनत की है।

आधुनिक दौर में भारत जैसे विशाल देश में किसी एक पद्धति के सहारे पूरी जनसंख्या की सेहत की रखवाली कर पाना आसान नहीं है। इसलिए होना तो यह चाहिए कि जिस पद्धति में जो कमी है, उसे स्वीकार करे और दूसरी पद्धति की अच्छाई को स्वीकार करे। लेकिन बात यहीं पर आकर अटक जाती है। आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा और होमियोपैथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति में विकसित सर्जरी की तकनीक को न सिर्फ स्वीकार करते हैं, बल्कि इस मोर्चे पर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति इस मामले में पूरी तरह असहिष्णु है। वह रिकॉर्ड पर दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती। यह बात और है कि पेट, हड्डी, नींद और रक्तचाप के विकार के संदर्भ में ऐसे अनेक लोगों के अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं कि बड़े आधुनिक अस्पतालों के डॉक्टरों ने जो दवाएं सुझाईं, वे अंग्रेजी नाम में ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाएं ही थीं।

विदेश में भी हुआ था विवाद = पारंपरिक बनाम आधुनिक चिकित्सा पद्धति की कथित श्रेष्ठता पर जारी विवाद के संदर्भ में याद दिलाना जरूरी है कि ब्रिटेन के पड़ोसी देश आयरलैंड में कोरोना की पहली लहर के दौरान विवाद हुआ था। आयरलैंड में फूलों और जड़ी-बूटियों से इलाज की परंपरा है। कोरोना के इलाज में जब आयरलैंड के डॉक्टरों ने इस पारंपरिक पद्धति का सहारा लिया तो वहां भी इसे अवैज्ञानिक और खतरनाक बताकर खारिज किया गया। यह बात और है कि इलाज के कथित प्रोटोकाल को आयरलैंड ने खारिज कर दिया और वह अपनी पारंपरिक पद्धति से भी इलाज करता रहा। नार्वे ने भी ऐसा किया और एलोपैथी के वर्चस्व वाले कथित प्रोटोकॉल तक को मानने से इन्कार कर दिया। कुछ अफ्रीकी देशों में तो फार्मा लॉबी के दबाव में पारंपरिक पद्धति से इलाज करने वालों को जेल तक में डाला गया। यह बात और है कि विरोध बड़ने के बाद फार्मा लॉबी को हथियार डालने पड़े।कथित वैज्ञानिकता की जब भी दुहाई दी जाती है, हमारे पास ब्रिटेन और अमेरिका के ही उदाहरण होते हैं।

हमारे यहां के आधुनिक विद्वान उन्हीं का आधार लेकर अपनी पारंपरिक ज्ञान परंपरा को खारिज करते हैं। ऐसे लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि पिछली सदी के सातवें दशक में अमेरिकी शुगर लॉबी ने खाने के तेल को फर्जी शोध के नाम पर धीरे-धीरे खाने की आदत से न सिर्फ दूर करा दिया था, बल्कि चीनी को उसके मुकाबले अच्छा ठहरा दिया था। वर्ष 2016 में अमेरिका के जेएएमए इंटरनल मेडिसिन में छपे एक लेख के मुताबिक उस समय अमेरिकी शुगर लॉबी ने चीनी से होने वाले रोगों मसलन मधुमेह, हृदय रोग आदि को गलत साबित करने और उसकी ओर से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए फर्जी शोध करा दिया था। इस आग्रही अध्ययन में विशेषज्ञों को तैयार किया गया कि वे दिल के रोगों के लिए सैचुरेटेड फैट यानी सांद्र वसा को जिम्मेदार ठहराएं। सैनफ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टैंटन ग्लैंट्ज ने चीनी उद्योग के गोपनीय दस्तावेजों के हवाले से यह पर्दाफाश किया था।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार

आर्थिक गैर-बराबरी भी बीमारी

पिछले साल मार्च में जब पूर्ण लॉकडाउन लगाकर और आजीविका पर होने वाले इसके नुकसान से आंखें मूंदते हुए मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, तब वे गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए थे। घर वापसी की उनकी वह लंबी यात्रा पहली लहर से मिली पीड़ा और कठिनाई का प्रतीक थी। एक साल बाद, आज आम जनमानस पर देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवा और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के भी परेशान होने की तस्वीरें हावी हैं। विडंबना यह है कि स्वास्थ्य संकट ने आजीविका के संकट को मानो गायब कर दिया है, जिसका भारत सामना कर रहा है। इससे वे आवाजें भी मंद पड़ गई हैं, जो एक साल पहले अपने अधिकारों के लिए मुखर थीं। यह इस बात का पैमाना है कि राष्ट्र किस आसानी से अपने लोगों को छोड़ देता है। दूसरी लहर में आजीविका के आसन्न संकट को समझने के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं और लोगों को दी जा रही राहत अब भी नाकाफी है। नतीजतन, देश का वंचित और गरीब तबका अब अपने मृत परिजन की सम्मानजनक अंतिम विदाई भी नहीं कर पा रहा।

दूसरी लहर ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जो कोविड-19 के कारण ढांचागत असमानता के गहराने के संकेत दे रही है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में देश में कामकाजी वर्गों की स्थिति का जायजा लेते हुए 'द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि 2020 में देश के अधिकांश श्रमिकों की आमदनी में तेज गिरावट दिखी है। गरीब परिवारों की कुल आमदनी में यह गिरावट काफी ज्यादा थी। अंतिम पायदान के 10 फीसदी घरों में 27 फीसदी कम पैसे आए। गरीबों की आमदनी कम होने से उपभोग पर खासा असर पड़ा है। 'हंगर वाच' नामक संस्था बताती है कि अक्तूबर, 2020 में उसने जो सर्वे किया था, उसमें भाग लेने वाले हर तीन में से एक ने 'कभी-कभी' या 'अक्सर' एक समय भूखे रहने बात कही थी, और 71 फीसदी परिवारों ने भोजन में पोषक तत्वों की कटौती की बात मानी थी।

लॉकडाउन के बाद के आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक गड़बड़ी को बेपरदा कर दिया, जिससे भारत पिछले साल निपटने में विफल रहा था। अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक, औपचारिक अर्थव्यवस्था में यह दिखा कि महामारी के दौरान सूचीबद्ध कंपनियां छोटी व असंगठित इकाइयों की कीमत पर फायदे कमा रही हैं, जबकि प्रतिकूल हालात में भी देश के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार छोटी व असंगठित इकाइयां देती हैं।

इस बेरोजगारी बड़ाते आर्थिक सुधार के कारण संगठित क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मी असंगठित क्षेत्र में काम करने को मजबूर हुए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईई के आंकड़ों के आधार पर 'द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल भारत के संगठित वेतनभोगियों में से लगभग आधे असंगठित क्षेत्र में चले गए। उन्होंने या तो खुद का काम शुरू किया (30 फीसदी), निविदा पर काम करना शुरू किया (10 फीसदी) या फिर वे बिना सामाजिक सुरक्षा वाले रोजगार से जुड़ गए (नौ फीसदी)। दिक्कत यह है कि सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कोई खास जतन नहीं किए।

मोदी मैजिक का परीक्षा वर्ष

दो साल पहले आज के दिन पूरा देश मानो 'मोदी मैजिक'में डूब-उतरा रहा था। शाम को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ लेते समय उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। वजहड़ 2014 के मुकाबले अधिक सीटें हासिल कर भाजपा राजग सहयोगियों के बिना भी हुकूमत चलाने में सक्षम थी। यह पहला भाजपा मंत्रिमंडल था, जिसमें 'स्वास्थ्य कारणों'से सुषमा स्वराज नहीं थीं। कल तक गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभालने जा रहे थे। उनकी जगह अमित शाह ने ले ली थी। तय था, आने वाले दिन आतिशी होने वाले हैं।

अगले कुछ महीनों तक ऐसा लगा, जैसे कोई रन-पिपासु बल्लेबाज मैदान के कोने-कोने पर छक्कों और चौकों की बारिश कर रहा है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। देश के नक्शे में लद्दाख नाम का एक नया केंद्र शासित प्रांत उदित हो चुका था और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा भी अतीत बन गया था। इससे पहले तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। अयोध्या में मंदिर-निर्माण का शिलान्यास सहित ये कुछ ऐसे फैसले थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी बरसों से बस घोषणाएं करती आई थी। नरेंद्र मोदी ने उन्हें अमलीजामा पहना दिया था। इसके साथ, उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर भी 2024 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। सरकारी बैंकों का डूबता कर्ज इसमें बड़ी बाधा था, लिहाजा 19 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का एलान किया गया। किसानों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद कृषि उत्पाद खरीदी के कानून बदल दिए गए। पिछली पहली फरवरी को पेश सालाना बजट में सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का रास्ता भी हमवार कर दिया गया। साफ था, मोदी मन मुआफिक आर्थिक सुधारों के लिए हर हाल में प्रतिबद्ध हैं। सब कुछ योजनानुसार चल रहा था, पर किसने सोचा था कि चीन में कहर मचा रहा कोरोना क्रूर दृष्टि से भारत को घूर रहा हैड़ इसी महामारी के कारण आज जब प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब उनके चारों ओर चुनौतियों की विशाल चट्टानें खड़ी हैं।

अगर हम तीसरे साल की तीन सबसे बड़ी चुनौतियों का आकलन करें, तो कोरोना अपनी निर्मम भयावहता के साथ सबसे आगे खड़ा नजर आता है। अब तक इस महारोग से भारत में आधिकारिक तौर पर 3,22,512 लोग मर चुके हैं। विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इन भयावह आंकड़ों के बीच विशेषज्ञ चेतावनी देते नजर आते हैं कि अभी तीसरी लहर आनी शेष है। वे यह भी कहते हैं कि अगर देश की 70 से 80 फीसदी आबादी को तत्काल प्रतिरोधी टीके नहीं लगे, तो ऐसी लहरें आगे भी आती रहेंगी। सरकार का दावा है कि दिसंबर तक सभी लोगों को टीका लगा दिया जाएगा, पर अभी तक सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। 18 या उससे अधिक वर्ष के समस्त नागरिकों के टीकाकरण की घोषणा तो कर दी गई, परंतु सैकड़ों की संख्या में टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। उन्हें कब इन प्राणरक्षक बूंदों की आपूर्ति होगी, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। तमाम सूबाई सरकारें इसके विरोध में मुखर हैं। उनका आरोप है, सरकार ने सियासी लाभ के लिए महामारी के खतरे की अनदेखी की। महामारियां देर-सबेर बीत जाती हैं, पर उनके दिए जख्म गहरे होते हैं। भारत की माली हालत पर इसने अभी से गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के मुताबिक, पिछली 23 मई को खत्म हुए सप्ताह में ग्रामीण बेरोजगारी दर 13.5 फीसदी पहुंच गई। यह कितनी तेजी से बड़ रही है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 9 मई को यह आंकड़ा 7.29 फीसदी था। शहरों में बेरोजगारी दर 17.4 फीसदी पाई गई और राष्ट्रीय बेरोजगारी दर भी नए सोपान चड़ती हुई 14.7 फीसदी पर पहुंच गई। अगर लॉकडाउन जल्दी नहीं खत्म हुए, तो स्थिति और भयावह हो सकती है। आंशिक लॉकडाउन और स्वास्थ्य खर्चों के चलते भारत के 'महान मध्यवर्ग'से 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे जाने को अभिशप्त हुए हैं।

तय है, मोदी को देशवासियों की प्राण-रक्षा के साथ बिगड़ती माली हालत को भी पटरी पर लौटाना होगा। इसी मुकाम पर उनकी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है। अगले वर्ष यानी 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा और मणिपुर में चुनाव हैं। इनका बिगुल अभी से बज चुका है। असम और पुडुचेरी में जीत के बावजूद पश्चिम बंगाल की पराजय ने भाजपा की सियासी महत्वाकांक्षाओं पर प्रश्न-चिह्न लगा दिया है। मोदी के दूसरे सत्ता-रोहण के बाद दस राज्यों में चुनाव हुए, भाजपा उनमें से सिर्फ चार में जीत सकी। इनमें भी सहयोगियों का किरदार काफी अहम था। यही वजह है कि कई राजनीतिक समीक्षक यह दावा करते हैं कि केंद्र में भले ही नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प न नजर आता हो, पर जहां कोई सबल सूबाई शक्ति सामने होती है, तो वोटर विधानसभा में उसे वरीयता देते हैं।

किसानों की दोगुनी आय पर संशय कोरोना से बेपटरी हो गईं योजनाएं

संवाददाता, भोपाल

कोरोना संकट काल में प्रदेश सरकार की एक के बाद एक कई योजनाएं बेपटरी हो गई हैं। यानी जिन उद्देश्यों को लेकर योजनाएं शुरू की गई थीं वे कोरोना काल में रुक गईं। आगे नहीं बढ़ सकीं। ऐसी ही एक योजना किसानों से संबंधित है। जिसमें खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि अधोसंरचना निधि योजना पर राज्य सरकार मिशन मोड में काम करने वाली थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रदेश के कई जिलों में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की वजह से गतिविधियों पर विराम लग गया है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि कृषि, सहकारिता और उद्यानिकी विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया था। कृषि विभाग की ओर से राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन के साथ ही कृषक उत्पादक समूहों को आंदोलन के रूप में विस्तारित करने के लिए कार्यक्रम तय कर लिया गया था।

तीन विभागों ने की थी तैयारी

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि अधोसंरचना निधि योजना के अंतगर्त शुरुआत में प्रत्येक विकास खंड से योजना के तहत कम से कम दो प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। सहकारिता विभाग की तरफसे भारत सरकार के उपक्रम नाबार्ड, एनसीबीसी के अधिकारियों को शामिल करते हुए सहकारिता विभाग अपेक्स बैंक और माकर्फेड के अधिकारियों की दो कमेटियों का गठन किया गया था। तय मापदंडों के मुताबिक जिला स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और विभिन्न समितियों को चिन्हित भी कर लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर प्रदेश में स्थितियां बदल गई हैं। कोरोना के कारण प्रदेश में सामान्य गतिविधियां लगभग ठप सी पड़ गई हैं।

मिशन मोड पर संचालित होनी थी योजना

राज्य सरकार कृषि अधोसंरचना निधि योजना को मप्र में मिशन मोड पर संचालित करने की तैयारी में थी। इस फंड के तहत किसानों को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से किसानों को उद्यमी बनाने के लिए नई व्यवस्था विकसित करने जा रही है जिससे कि किसानों को उद्यमी बनने में मदद मिल सके। इसके लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों, किसान उत्पादक समूहों, स्व-सहायता समूहों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के साथ ही केंद्रीय राज्य एजेंसियां या सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना को कर्ज लेने के लिए पात्रता होगी।

ब्याज पर मिलेगी छूट

खास बात है कि इन सभी पात्र संस्थाओं को तीन प्रतिशत ब्याज पर छूट अगले सात वर्ष की अवधि के लिए मिल सकेगी। साथ ही कृषि अधोसंरचना के तहत ही उन्नत सीड ग्रेडिंग प्लांट, वैक्यूम व्हीट पैकिंग यूनिट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज विकसित किया जाना है। प्रदेश में एक जिला एक पहचान के तहत विभिन्न जिलों में सब्जियों और फ्लों के उत्पादन की अधिकता का लाभ लेते हुए प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जाएंगी। वर्तमान में उत्पादन अधिक हो जाने से उत्पाद की कीमत कम हो जाने की स्थिति में किसान लाभान्वित नहीं हो पाता है। यही वजह है कि उद्यानिकी विभाग ने पैकहाउस, कोल्ड रूम, इंटीग्रेटेड हाउस, इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई, मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉर्टिंग्स एंड ग्रेडिंग के प्रकरण तैयार किए गए हैं।

कृषि में बड़े बदलाव की योजना

प्रदेश में किसानों को खेती के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिल रहा है, लेकिन अब खेती से जुड़े व्यवसाय के लिए भी उन्हें सस्ता कर्ज मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें तीन फीसदी तक ब्याज में छूट मिल सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए कृषि अधोसंरचना फंड स्थापित किया है। इस फंड में सात हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इतनी बड़ी राशि के फंड से कृषि से जुड़ी संस्थाओं को रियायती दामों पर कर दिया जाएगा। इन संस्थाओं, समितियों और समूहों को दो करोड़ रुपए तक का कजर्ज दिया जाएगा।

सस्ते कर्ज पर लगा ब्रेक

दूसरी ओर कोरोना का असर बैंकों के कामकाज पर भी साफदिखाई दे रहा है। इस कारण योजना के तहत किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की योजना अपना स्वरूप लेने में सफ्ल नहीं हो सकी है। ऐसे में राज्य सरकार को अब 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा।

तीन लाख किसानों को मिले चार-चार हजार

इधर, कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीते रोज भले ही किसानों को सम्मान निधि के रूप में दो- दो हजार रुपए की आठवीं किस्त जारी की गई है, लेकिन मप्र ऐसा राज्य है जिसके करीब तीन लाख किसानों को दो की जगह चार हजार रुपए बतौर किस्त के रूप में मिले हैं। यह वे किसान हैं जो किसी न किसी कारण से पिछली किस्त पाने से वंचित रह गए थे। इसकी वजह से इन किसानों के खाते में सातवीं और आठवीं किस्त के रूप में एक साथ चार हजार रुपए का भुगतान किया गया है। खास बात यह है कि किसानों को सम्मान निधि की राशि ऐसे समय प्रदान की गई है, जब कोरोना की वजह से सभी परेशान चल रहे हैं। इस राशि के मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। यह बात अलग है कि इस समय किसानों की फसल आ चुकी है और उसकी सरकार द्वारा खरीदी की जा रही है, लेकिन इस फसल का पैसा अभी किसानों के खातों में नहीं आया है।

गोबर और पराली से रायसेन में बनेगी बॉयो सीएनजी

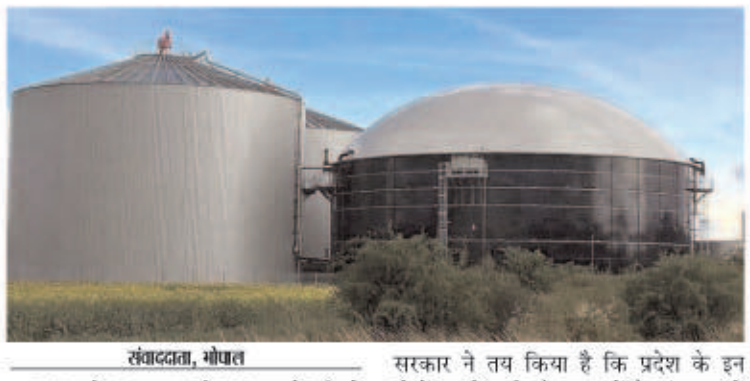

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार की अब रायसेन जिले में गोबर और पराली से बायो सीएनजी बनाने की योजना है। इससे न केवल प्रदूषण को बचाया जा सकेगा बल्कि इससे बनने वाले खाद की वजह से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। शुरुआती दौर में इसके लिए रायसेन जिले के दो बड़े गौ अभ्यारण्यों का चयन किया है। इनमें सलारिया और कामधेनू गौ अभ्यारण्य शामिल हैं। गुजरात की निजी कंपनी की मदद से सरकार द्वारा इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके लिए सरकार स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार यह कदम गुजरात में बनाई जा रही इसी तजर्ज पर बॉयो सीएनजी गैस की सफ्लता को देखते उठाने जा रही है। खास बात यह है कि इस प्लांट में बॉयो गैस तो बनेगी ही साथ ही सालिड और लिक्विड खाद भी बड़ी मात्रा में तैयार होगा।

सीएम ने दी सहमतिः इस योजना पर काम करने के लिए गुजरात की भारत बॉयोगैस एनर्जी नामक कंपनी ने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। कंपनी द्वारा शुरुआती पांच सालों तक इन प्लांटो का संचालन किया जाएगा। इसके लिए फ्लिहाल शुरुआती तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा भी सहमति प्रदान कर दी गई है।

गुजराती संस्था संभालेगी गौशाला : सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के इन दोनों सबसे बड़ी गौ शालाओं के संचालन में निजी संस्थाओं की मदद ली जाए। इसके लिए सरकार स्तर से गुजरात की अक्षय नामक संस्था का चयन किया गया है। यह संस्था बड़ी मात्रा में गुजरात में गौशलाओं का संचालन करती है। सरकार की मंशा सलारिया गौर अभ्यारण्य में उसकी क्षमता के हिसाब से दस हजार गौ वंश रखने की है। वतर्ज्मान में यहां पर चार हजार गौ वंश ही हैं। यही नहीं सलारिया गौ-वंश की मौतों को लेकर भी बेहद बदनाम है।

कहां कितनी बनेगी गैसः सलारिया स्थित गौ अभ्यारण्य में लगने वाले प्लांट में हर रोज तीन हजार मीट्रिक टन बायो गैस, 25 मीट्रिक टन सॉलिड आगेर्ज़निक खाद और सात हजार लीटर लिक्विड खाद का भी निमार्ण होगा। इसके लिए प्रतिदिन प्लांट के लिए 70 मीट्रिक टन गोबर, पराली , घास और अन्य तरह के कचरे की जरुरत रहेगी। इसी तरह से दूसरे अभ्यारण्य में हर दिन चार सौ किलोग्राम बायोगैस, 3 मीट्रिक टन सॉलिड और एक हजार लीटर लिक्विड आगेर्ज़निक खाद का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्लांट को हर दिन 10 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल की जरुरत पड़ेगी। इस तैयार होने वाली गैस के साथ ही खाद को बाजार में आम लोगों को विक्रय किया जाएगा।

'स्वामित्व' का काम दूसरे राज्यों के लिए बना रोल मॉडल

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार ने कम संसाधनों और कोरोना महामारी के बीच कई ऐसे काम किए हैं जिनकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। यही नहीं, यहां के कम्प्यूटराइजेशन की भी देशभर में सराहना मिली। इसी तरह का काम स्वामित्व योजना के अंतगर्त भी हुआ है जिसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली, बल्कि यह योजना अब दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई है। दरअसल, कम संसाधनों के बीच कंप्यूटराइजेशन को लेकर जो काम प्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर हुआ है, उसके बाद देश के पांच अन्य राज्यों ने मध्यप्रदेश के अफसरों से इस दिशा में किए गए काम की प्लानिंग की जानकारी मांगी है। इनमें उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्रप्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य शामिल है। गौरतलब है कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत पिछले साल बीस जिलों का चयन किया गया था। इस साल भी दस जिलों में काम शुरू हो गया है।

14 जिलों में चल रहा सर्वेः जिन जिलों में ड्रोन सर्वे का काम चल रहा है, वहां 3542 आबादी ब्लॉक का काम हो चुका है। खास बात यह है कि इसमें उन्नीस सौ से अधिक नक्शे संशोधन में जा चुके हैं। वहीं 792 ग्राम प्रकाशित किए गए हैं। अभी ड्रोन के द्वारा सवेज़ का काम खरगोन, मुरैना, विदिशा, सागर, हरदा, सीहोर, श्योपुर, दतिया, रतलाम, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, धार और डिंडोरी आदि जिलों में चल रहा है।

मप्र को मिला मौकाः प्रदेश में स्वामित्व योजना में चल रहे आबादी सवेज़ के काम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है। जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है और मप्र को इस पर प्रजेंटेशन का मौका मिला है। आबादी क्षेत्र की भूमि में स्वामित्व अधिकार देने के लिए ड्रोन कैमरे से किए जा रहे कंप्यूटराइजेशन की मॉनिटरिंग खुद आयुक्त भू अभिलेख (सीएलआर) कर रहे हैं।

इनका कहना है

मप्र में अब तक 1560 स्वामित्व दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं। जिसमें से 1433 में खसरा देने की कार्यवाही भी हो गई है। इस भूमि, भवन के स्वामी अब स्वामित्व का अधिकार मिलने के बाद अपनी संपत्ति को बंधक रखने, बेचने का काम कर सकते हैं। स्वामित्व योजना में इन एसेट को कैपिटल बना दिया गया है।

-ज्ञानेश्वर पाटिल, आयुक्त, भू-अभिलेख

हरियाली लाने तैयार हो रहा 'बीज बम'

बारिश से फटेगा बम, आएगी हरियाली

जावेद अली, मंडला

मंडला के कृषि विज्ञान केंद्र में इन दिनों वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। यहां के वैज्ञानिक और कर्मचारी बीज बम बनाने में जुटे हुए हैं। बम का नाम सुनकर हम भले ही घबरा जाते हो लेकिन यह बम प्रकृति को हरा-भरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मानसून सीजन में इस बम को सिर्फ फेंकना होगा और बस तैयार हो जाएंगे पौधे। मंडला कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम जो मिट्टी, पानी और खाद को मिलाकर गोले बना रहे हैं, ये कोई आम मिट्टी के गोले नहीं है बल्कि बीज बम हैं।

दरअसल, लगातार घट रहे वनों के क्षेत्रफल और इसके चलते हो रहे वातावरण में बदलाव को देखते हुए वृक्षारोपण की सलाह दुनिया के सभी पर्यावरण विशेषज्ञ दे रहे हैं। वैसे तो हर साल मानसून के दौरान वृक्षारोपण होते हैं लेकिन उनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। इस समस्या को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख विशाल मेश्राम, इन दिनों बड़ी संख्या में बीज बम बना रहे हैं।

बारिश के बाद खुद तैयार हो जाएंगे पौधे

एक बम में रहेंगे दो बीज

बम का नाम सुन कुछ अटपटा लगे तो आपको बता दें इन बीज बमों को सीड बॉल और अर्थ बॉल भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ड खाद, खेत की मिट्टी की मदद से ऐसी बॉल बनाई हैं जिनमें किसी भी पेड के 2 बीज रखे गए हैं। खासकर इसमें सामुदायिक वानिकी के अंतरगत आने वाले वृक्ष के बीज जैसे नीम, हर्रा, बहेड़ा, कनाडा पुनीठ का लेख उनआंवला जैसे दीर्घकालिक वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

वृक्षारोपण की जगह पर गिराया जाएगा बम

मानसून के मौसम में 2 से 3 बरसात के बाद किसी भी ऐसे स्थान पर जहां वृक्षारोपण करना है, वहां फेंकना है। इसके बाद ये बॉल बाकी का काम खुद कर देंगे। पानी मिलते ही इस बॉल के बीज अंकुरित हो जाएंगे और इसकी केंचुआ खाद और मिट्टी इन्हें ब? होने में मदद करेगी। इतना ही नहीं यदि आप घर में इन्हें लगाना चाहते है तो केवल इसे उस जगह रख दीजिये जहां आप पौधा लगाना चाहते है। यह वृक्षारोपण का सबसे आसान तरीका है और नर्सरी मे बीज लगाने, पौधे की देखरेख करने और फिर बाद में गड्ढे खोद कर रोपने से लोगों को राहत दिलाएगी। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विशाल मेश्राम बताते है कि इसका नाम बीज बम इसलिए दिया गया है क्योंकि हर अटपटे नाम के पीछे लॉजिक यह होता है कि अटपटे नाम की वजह से आकर्षण पैदा हो। यदि अटपटा नाम नहीं होता तो लोग आकर्षित नही होते। जब लोग आकर्षित होते हैं तो जानने की कोशिश करते है कि यह क्या है। इस वजह से लोगों मे जिज्ञासा पैदा होती है। विकास की अंधी दौड़ के कारण वन लगातार घटते जा रहे है. हमें वृक्ष बढ़ाने की जरूरत है जो ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से मिलती थी वह मिलती रहे। वर्षा भी अनियमित हो रही है, उससे उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसलिए बीज बम बनाने का प्रयास किया जा रहा है. बीज बम बनाना भी काफी आसान है। इसके लिए खेत की मिट्टी की आवश्यकता है. खेत की मिट्टी, पानी और खाद मिलाकर गोले तैयार किये जाते हैं. इन गोलों में बीज डाल दिए जाते हैं। यह दो तरीके से काम करता है या तो उसको फेंका जाता है फिर जहां वृक्षारोपण करना, वहां इसको रख दिया जाता है। मानसून आने के पश्चात जब इस मे नमी होगी उससे बीजो का अंकुरण होगा और पौधे तैयार हो जाएंगे। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इसमे 70फीसदी सफलता मिली हुई है।

कैंसर, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए 'संजीवनी' काला गेहूं

- **अच्छी खबर:** भोपाल के अन्नदाता भी करने लगे काले गेहूं की खेती
- **पंजाब:** नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने किया विकसित
- सेहत के साथ ही किसानों के लिए भी लाभदायक काला गेहूं की खेती
- विशेषज्ञों का दावा- साधारण गेहूं के मुकाबले 60 फीसदी आयरन ज्यादा

संवाददाता, भोपाल

खेती-किसानी के क्षेत्र में अपने नए-नए प्रयोगों को लेकर दूसरे राज्यों का रोल मॉल बने मप्र के किसान आब कैंसर, डायबिटीज और हार्ट पेशेंटों के लिए संजीवनी भी उगाने लगे हैं। जी हां, मप्र के अधिकांश जिलों में अब काले गेहूं की खेती होने लगी है।

सात बरसों के रिसर्च के बाद गेहूं की इस नई किस्म को पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (नाबी) ने विकसित किया है। इसकी बालियां भी आम गेहूं जैसी हरी होती हैं, पकने पर दानों का रंग काला हो जाता है। यहां के कई किसानों ने मोहाली से इसके बीज लाकर खेतों में बोवनी की थी। ईंटखेड़ी स्थित फ्ल अनुसंधान केंद्र से भी इसके बीज का वितरण किया गया था। दरअसल, धार, बड़वानी, नीमच और मंदसौर के बाद अब भोपाल और उससे सटे क्षेत्रों के खेतों में भी काले गेहूं की पैदावार होने लगी है। विशेषज्ञों का दावा है कि इसमें कैंसर, डायबिटीज, तनाव, हृदयरोग और मोटापे जैसी बीमारियों की रोकथाम करने की क्षमता है।

काले गेहूं के फायदे

कब्ज को दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है नियमित करता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद है। हाटज के पेशेंट को भी लाभ पहुंचाता है। मोटापा कम करने में मदद करता है। कैंसर कारकों को कम करता है।

तीन गुना ज्यादा कमाया

भोपाल से सटे श्यामपुर के बिछिया गांव के किसान महेश कुमार ने अपने खेत में यह गेहूं बोया था। वे एक फसल ले चुके हैं। महेश कहते हैं सामान्य गेहूं की तुलना में हम इससे 2-3 गुना ज्यादा लाभ कमा रहे है।

मोहाली से लाए थे बीज: बैरसिया के इचगिरी गांव के किसान राजमल सिंह ने डेढ़ एकड़ में यह गेहू बोया है। इसके बीज पंजाब के मोहाली से लेकर आए थे।

देश के पास इसका पेटेंट: चंडीगढ़ के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट (एनएबीआई) के सात सालों के शोध के बाद काले गेहू का पेटेंट कराया गया है। एनएबीआई ने इस गेहू का नाम नाबी एमजी दिया है।

इनका कहना है

गेहू के काले रंग की वजह एंथोसाएनिन है। फलो, सब्जियों और अनाजों के रंग उनमें मौजूद प्लांट पिगमेंट की मात्रा पर निभर्र होते है। काले गेहू मे एंथोसाएनिन नाम के पिगमेंट होते हैं। इसकी अधिकता से फलों, सब्जियों, अनाजों का रंग नीला, बैंगनी या काला हो जाता है। एंथोसाएनिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह गेहू सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। किसानों को इसका भाव भी सही मिल जाता है।

डॉ. एमएस परिहार, चीफसाइंटिस्ट, फल अनुसंधान केंद्र

काले गेहू मे पाया जाने वाला कटेंट शुगर, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। साधारण गेहू में एंथोसाएनिन सिर्फ 5पीपीएम होता है, लेकिन काले गेहू में यह 100 से 200 पीपीएम होता है। इसके अलावा काले गेहू में जिंक और आयरन की मात्रा मे भी अंतर होता है। साधारण गेहू की तुलना मे इसमें 60 फीसदी आयरन ज्यादा होता है। प्रोटीन, स्टार्च और दूसरे पोषक तत्व समान मात्रा में होते हैं।

डॉ. अशोक वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के डिपाटमेंट ऑफएग्रीकल्चर

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र.
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)